इकाई 16 ग्रामीण विकास के लिए विस्तार में अर्थशास्त्र रणनीति

इकाई की रूपरेखा

16.0 लक्ष्य और उद्देश्य

16.1 परिचय

16.2 भारत में ग्रामीण गरीबी

16.2.1 ग्रामीण विकास प्रयास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था

16.3 विकास की अवधारणा

16.4 आर्थिक रणनीति

16.4.1 विस्तार में आर्थिक रणनीति

16.5 ग्रामीण विकास पर विस्तार कर्मियों द्वारा आर्थिक हस्तक्षेप

16.5.1 प्रधानमंत्री जन–धन योजना (MPJDY)

16.5.2 अटल पेंशन योजना (APY)

16.5.3 किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना

16.5.4 कृषि विज्ञान केंद्र (ज्ञटज्ञ)

16.5.5 एमपी किसान सम्मान निधि योजना

16.5.6 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

16.5.7 दीन दयाल अंत्योदय योजना – एनआरएलएम

16.5.8 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

16.5.9 अम्ब्रेला एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)

16.5.10 जनजातीय लोगों के लिए योजना

16.5.11 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (MPAGY)

16.5.12 महिला सशक्तिकरण योजनाएं

16.5.13 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

16.6 आइए हम संक्षेप में बताएं

16.7 मुख्य शब्द

16.8 पढ़ने का सुझाव दिया

16.9 अपनी प्रगति की जांच करने के लिए उत्तर

16.0 लक्ष्य और उद्देश्य

वर्तमान इकाई का उद्देश्य आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विस्तार कर्मियों द्वारा आर्थिक हस्तक्षेप के व्यावहारिक दायरे की ओर उन्मुख करना है। इस प्रक्रिया में, ग्रामीण गरीबी की वर्तमान स्थिति और विकास की अवधारणा और आर्थिक रणनीति पर भी संक्षेप में चर्चा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत, विस्तार कर्मी विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में मदद करके आर्थिक हस्तक्षेप प्रदान कर सकते हैं।

इकाई के अंत तक, आपको निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए:

- भारत की ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति का उल्लेख कीजिए;
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की रणनीतियों का वर्णन किया; और
- ग्रामीण आर्थिक रणनीति को लागू करने के लिए विस्तार कर्मियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक हस्तक्षेप की पहचान करें।

16.1 परिचय

भारत मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है। देश की लगभग 68.8 प्रतिशत आबादी और 72.4 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं (जनगणना 2011)। जनसंख्या पूर्वानुमान बताते हैं कि 2050 तक, भारत में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों वर्चस्व रहेगा। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों का पलायन शहरी क्षेत्रों पर नौकरी के लिए दबाव बनाता है, जिससे कई ग्रामीण प्रवासियों को कम मजदूरी पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय के अंतर को कम करें, जो हमेशा से अधिक रहा है। भारतीय शहरों की तुलना में, इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बहुत अधिक विकास दर की आवश्यकता है। परंपरागत रूप से, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार का प्राथमिक क्षेत्र रहा है। अधिक उत्पादक गैर–कृषि क्षेत्र में कृषि को ग्रामीण क्षेत्रों और पूरी अर्थव्यवस्था में एक आवश्यक आर्थिक विकास स्रोत और परिवर्तन के रूप में देखा जाता है।

16.2 भारत में ग्रामीण गरीबी

गरीबी उन्मूलन स्वतंत्रता के बाद से ही एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। यह गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की राष्ट्रीय विकास योजना के मूल में है, जो गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को डिजाइन, कार्यान्वित और निगरानी के लिए एक प्राथमिक इनपुट के रूप में है। समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन रणनीतियों की कम के बैरोमीटर के रूप में सेवा करने के लिए गरीबी माप भी आवश्यक है। गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार के पास बुनियादी जीवन स्तर का समर्थन करने के लिए वित्तीय साधनों की कमी होती है। 2011 में भारत की ग्रामीण गरीबी दर 25.7 प्रतिशत थी। यह समय के साथ कम हो गया, 1993 में 50.1 प्रतिशत से घटकर 2011 में 25.7 प्रतिशत हो गया।

अपनी प्रगति की जाँच करें 1

नोटः 1) नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) आपको अभ्यास पूरा करने के लिए मॉडल उत्तर से परामर्श नहीं करना चाहिए

i) गरीबी क्या है?

....

....

....

16.2.1 ग्रामीण विकास प्रयास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था

दशकों से, भारतीय गांव ने आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में काम किया है। स्वतंत्रता के बाद के युग में ग्रामीण पुनर्निर्माण और विकास आर्थिक नियोजन का एक मुख्य जोर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है क्योंकि कृषि अधिकांश ग्रामीण आबादी को रोजगार देती है। कृषि देश की आर्थिक रीढ़ है। देश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, आपूर्ति और विपणन, ग्रामोद्योग, ग्रामीण नेतृत्व, ग्राम प्रशासन, आदि सभी में सुधार हुआ है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मदद से, एक कृषक अपने कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। ये किसान अब आधुनिक कृषि उपकरणों और बीज और उर्वरकों की उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग कर रहे हैं। आम राय के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत तक आबादी रहती है। कृषि, स्व–रोजगार, सेवा, विनिर्माण और अन्य ग्रामीण गतिविधियां भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्राथमिक क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता हैं।

16.3 विकास की अवधारणा

सभी ग्रामीण विस्तार कार्य एक विकास प्रक्रिया के भीतर होते हैं और इसे एक पृथक गतिविधि नहीं माना जा सकता है। विस्तार एजेंट और विस्तार कार्यक्रम और परियोजनाएं ग्रामीण समाजों के विकास का हिस्सा हैं। इसलिए, विकास शब्द को समझना और यह देखना आवश्यक है कि इसकी व्याख्या ग्रामीण विस्तार कार्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। विकास जटिल रूप से पूरी सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ कार्रवाई या हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ है। यह एक जटिल शब्द है जो पहले की स्थिति में बदलाव या प्रस्थान को दर्शाता है। ग्रामीण विकास के तीन तत्व हैं:

1) **आर्थिक** : किसी भी समाज के आर्थिक या उत्पादक आधार का विकास जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सामग्रियों का उत्पादन करेगा।

2) **सामाजिक** : समाज की गैर–उत्पादक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई सामाजिक सुविधाओं और सेवाओं (उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण) का प्रावधान।

3) **मानव** : लोगों की पूरी क्षमता का एहसास करने, उनके कौशल और क्षमताओं का उपयोग करने और अपने समुदाय को आकार देने में रचनात्मक रूप से योगदान करने के लिए लोगों का मानवीय और सांप्रदायिक रचना

उपरोक्त तीन तत्व विकास में भूमिका निभाते हैं। इसे दूसरों के नुकसान के लिए विशेष रूप से एक कारक पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। किसी भी समाज की आर्थिक नींव महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधनों का उत्पादन करना चाहिए। हालांकि, हमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए और विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद करना है।

ग्रामीण विकास का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण लोगों की भागीदारी के साथ ग्रामीण जीवन में सुधार करना है। स्थानीय क्षेत्र में संस्कृति, इतिहास, भाषा और अन्य प्रचलित मुद्दे बाहरी व्यक्ति के लिए विदेशी हो सकते हैं। इस प्रकार, ग्रामीण लोगों को स्वयं अपने सतत ग्रामीण विकास में भाग लेना चाहिए।

अपनी प्रगति की जाँच करें 2

नोटः 1) पाठ से परामर्श किए बिना प्रश्न का उत्तर दें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें

1) ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है?

....

....

....

....

....

16.4 आर्थिक रणनीति

रणनीति अनिश्चित परिस्थितियों में एक या अधिक दीर्घकालिक या समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य योजना है। चूंकि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन आम तौर पर छोटे होते हैं, इसलिए रणनीति आवश्यक है। उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों का निर्णय लेना, और गतिविधियों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना सभी एक रणनीति का हिस्सा हैं। एक योजना यह बताती है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा। जैसा कि एक संगठन अपने वातावरण के अनुकूल होता है या प्रतिस्पर्धा करता है, इसे योजनाबद्ध किया जा सकता है या एक संचालन पैटर्न के रूप में उभर सकता है। इसमें अन्य चीजों के अलावा रणनीतिक योजना और रणनीतिक सोच शामिल है।

हेनरी मिंट्जबर्ग ने रणनीति नियोजन के विपरीत निर्णयों की एक धारा में एक पैटर्न के रूप में रणनीति को परिभाषित किया। इसके विपरीत, हेनरिक वॉन शेल के अनुसार, रणनीति की प्रकृति ऐसे वे व्यवहार हैं जो अर्थ का एक विशेष संयोजन प्रदान करते हैं – प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अलग या लग तरीके से गतिविधियों का संचालन करना पसंद करते हैं। डॉ व्लादिमीर क्विट रणनीति को "एक सिद्धांत खोजने, तैयार करने और विकसित करने की एक प्रणाली" के रूप में परिभाषित करते हैं जो ईमानदारी से पालन करने पर दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करेगा आर्थिक रणनीति में विशिष्ट मुद्दों/समस्याओं को संबोधित करने और उनके दीर्घकालिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ग्राहकों को अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों और तरीकों को लागू करना शामिल है। ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट आर्थिक रणनीतियों की आवश्यकता होती है जो सभी हितधारकों को संलग्न करती हैं, नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और अंततः उत्पादकता में सुधार करती हैं। आर्थिक संकट में एक सहयोगी रणनीति महत्वपूर्ण है, इसके लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करने

और असतत सिफारिशों की लंबी सूची से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। यहां विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अपनी प्रगति की जांच करें 3

नोटः 1) नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें

1) आर्थिक रणनीति शब्द की व्याख्या कीजिए?

....

....

....

....

....

16.4.1 विस्तार में आर्थिक रणनीति

विस्तारवादी ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं बशर्ते एक विशिष्ट नीति उनका मार्गदर्शन करे। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनमें विस्तार एक भूमिका निभा सकता है, उन पर आगे चर्चा की गई है।

खाद्य सुरक्षा को उपलब्धता, पहुंच और खाद्य भोजन (यूएसएआईडी 1995) के रूप में जाना जाता है, जैसा कि रिवेरा और कमर (2003) द्वारा उद्धृत किया गया है।

खाद्य उपलब्धता तब प्राप्त होती है जब एक राष्ट्र के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए नियमित रूप से पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है। घरेलू उत्पादन, अन्य घरेलू आउटपुट, औद्योगिक आयात, या खाद्य सहायता सभी का उपयोग ऐसे भोजन प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

भोजन तक पहुंचः जब परिवारों और व्यक्तियों के पास पौष्टिक आहार के लिए पर्याप्त भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, तो भोजन की पहुंच की गारंटी होती है। पहुंच घर की आय, परिवार के भीतर आय वितरण और भोजन की लागत से निर्धारित होती है।

खाद्य उपयोग भोजन का उचित जैविक उपयोग है, जिसमें पर्याप्त ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्व, पीने योग्य पानी और पर्याप्त स्वच्छता प्रदान करने वाले आहार की आवश्यकता होती है। प्रभावी खाद्य उपयोग खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण तकनीकों के परिवार के भीतर ज्ञान पर निर्भर करता है। (भोजन की हानि के दौरान भंडारण, रख–रखाव)।

सफल खाद्य सुरक्षा और गरीबी–उन्मुख कार्यक्रम ग्रामीण आबादी को अधिक और विविध उत्पादों का उत्पादन करने और विपणन योग्य अधिशेष का उत्पादन करने में मदद करते हैं। यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आय उत्पन्न करता है।

विस्तारवादियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो तकनीकी ज्ञान और संचार कौशल को जोड़ता है। वे इस ज्ञान को खेती और कृषि पैदावार में सुधार और गरीबी को कम करने के लिए लागू कर सकते हैं (न्यूचौटल ग्रुप, 2008)।

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षणः आम तौर पर, किसानों के पास संसाधनों को संरक्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। एक विस्तारवादी किसानों को प्राकृतिक संससाधनों के संरक्षण में मदद करने के लिए अनुनय रणनीतियों का पालन करता है

सहायक जानकारी का प्रसारः किसानों को विस्तारवादियों द्वारा नए तरीकों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है क्योंकि वे अनुसंधान और निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। विस्तारवादियों को विभिन्न ज्ञान तक पहुंच होनी चाहिए जो किसानों को आर्थिक विकास के लिए आवरूयक है। यदि आवश्यक हो तो वे अपने कार्यों के आधार पर इसका विस्तार कर सकते हैं। किसानों को प्रसारित विस्तार में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाजार–आधारित फसल योजना, बाजार की जानकारी, छोटे उद्यमों का विकास और नए आर्थिक उद्यम की खोज शामिल हो सकती है।

परियोजनाओं की स्थिरता : विस्तारवादियों के पास लोगों के कार्यों से निपटने का बहुत अनुभव है। यदि वे अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं। परियोजनाओं को टिकाऊ होने का अधिक सभावना है (रोलिंग, 1988)। जैसे ही सरकार अपना वित्तपोषण वापस लेती है, कई सरकारी परियोजनाएं अस्थिर हो जाती हैं, जो काफी चुनौती पूर्ण है। समस्या अतीत में स्वामित्व और समूह गतिशीलता से संबंधित रही है। किसान समूहों को शिक्षित करने के बाद, स्वामित्व के मुद्दों को समझना आसान है। यदि विस्तारवादी अपनी क्षमता का प्रयोग करें तो परियोजनाओं के टिकाऊ होने की अधिक संभावना होगी

कृषि समूहों का सशक्तिकरण : विकास के समर्थकों के अनुसार, स्थानीय लोगों का ''सशक्तिकरण'' ग्रामीण विकास के लिए सबसे उचित उद्देश्य है। इस विस्तार से गरीब किसान संगठनों की मानव संसाधन क्षमता और मूल्यवान विस्तार सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं सहायता समूह की क्षमताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। संसाधन–गरीब किसान समूहों में से कई के पास अनुभवहीन शासन और नेतृत्व है। विस्तारवादी किसान संस्थान बना सकते हैं, किसानों को संघों में संगठित कर सकते हैं और अन्य सहकारी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं क्योंकि वे स्थानीय संगठनात्मक विकास में अच्छी तरह से योग्य हैं।

भारत में ग्रामीण सहकारी समितियां : भारत में सहकारी समितियां दुनिया की सबसे व्यापक ग्रामीण वित्त प्रणालियों में से एक का हिस्सा हैं। बदलती अर्थव्यवस्था के साथ, भारत में कृषि सहकारी समितियों में अभी भी सुधार के लिए बहुत जगह है। किसान कई लोगों (छोटे और सीमांत किसानों) तक पहुंचकर कई ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। और गरीबी रेखा के नीचे के लोग। ग्रामीण इलाकों में कृषि सहकारी समितियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में, लगभग 4.5 लाख सहकारी समितियां हैं जिनकी कुल सदस्यता 220 मिलियन नागरिकों की है। सहकारी समितियां बीसवीं शताब्दी की हैं। अपनी शुरुआत में, उन्होंने मुख्य रूप से किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया, खासकर कटाई और बुवाई के दौरान। आज, सहकारी समितियां अधिकांश ग्रामीण ऋण को संभालती हैं, जो 65 प्रतिशत है। भारत की विभिन्न सहकारी समितियों के तहत, क्रेडिट सहकारी एक शक्तिशाली भारतीय प्रणाली है, जिसमें ग्रामीण ऋण सहकारी संगठन शामिल है। इसके अलावा, भारत के गांवों में। अन्य प्रकार की सहकारी समितियां किसान सेवा की समितियां और बड़े पैमाने पर कृषि के लिए बहुउद्देशीय समुदाय हैं। ग्रामीण सहकारी समितियां भी खरीद गतिविधि के माध्यम से अधिकतम मूल्य वसूलकर किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान वितरित करने में लगी हुई हैं। विस्तार का ज्ञान सहकारी समितियों की स्थिरता का समर्थन करके उस आर्थिक उद्यम में मदद करता है।

स्व–सहायता समूह प्रबंधन : भारत में, ''स्वयं सहायता समूह'' को गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में लिया जाता है। स्वयं सहायता समूह लगभग 33 मिलियन भारतीय महिलाओं को कम लागत वाली वित्तीय सेवाएं और अन्य गतिविधियां प्राप्त करने में सहायता करते है। ग्रामीण भारत में महिलाएं, विशेष रूप से निचली जातियों और निम्न शिक्षा स्तर के साथ, प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थिति और वित्तीय उत्पादों को प्राप्त करने की सीमा जैसी दुर्दशा का सामना कर रही हैं। भारत की ग्रामीण विकास पहल सूक्ष्म ऋण प्रदान करके महिलाओं की आर्थिक स्थिति और अन्य कमजोर लोगों के विकास पर केंद्रित है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह का अस्तित्व बाधाओं को जीतने के लिए कमजोर समूह, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना है। विस्तार समूह गठन, गतिशील समूह प्रबंधन, एसएचजी की स्थिरता के लिए समूह लामबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल स्थायी समूह ही अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें 4

नोटः 1) नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) किसानों को सशक्त बनाने में विस्तार कर्मियों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करें।

....

....

....

....

....

16.5 ग्रामीण विकास पर विस्तार कर्मियों के लिए आर्थिक हस्तक्षेप का दायरा

ग्रामीण विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम हैं। इन योजनाओं के तहत, विस्तार कर्मियों के लिए उचित आर्थिक हस्तक्षेप देने के लिए कई अवसर हैं। आर्थिक हस्तक्षेप परिणाम के साथ हस्तक्षेप कर रहा है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए एक स्थिति या प्रक्रिया। ग्रामीण लोगों के आर्थिक विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप विस्तार कर्मियों द्वारा सही और प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। उन हस्तक्षेपों के बिना, ग्रामीण लोगों को बेहतर बनाने के लिए उन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करना असंभव है। नीचे कुछ कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है जहां विस्तार कर्मी आर्थिक हस्तक्षेप दे सकते हैं।

16.5.1 प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई)

''प्रधान मंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई)'' का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों को वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच हो, जैसे कि बुनियादी बचत बैंक खाते, आवश्यकता–आधारित क्रेडिट, प्रेषण, बीमा और पेंशन। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन करना है। इस योजना से लाभान्वित होने के लिए, लोगों

को योजना की प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। विस्तार कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के बीच योजना द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्य और लाभों से संबंधित जागरूकता पैदा कर सकते हैं। साथ ही, वे प्रत्येक बैंक के लिए सेवा क्षेत्र की मैपिंग के लिए बैंक नेटवर्क के साथ दूरदराज के क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं। विस्तार कार्यकर्ता जानते हैं कि ग्रामीण लोगों के पास अन्य हितधारकों की तुलना में बेहतर है, इसलिए सेवा क्षेत्र का चयन अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा। डेबिट कार्ड, रूपे कार्ड का उपयोग करके, योजना से लाभ उठाने के लिए बैंक में खाता खोलना भी, एक्सटेंशन लोगों द्वारा भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 5

नोटः 1) पाठ से परामर्श किए बिना प्रश्नों का उत्तर दें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) उस क्षेत्र की पहचान करें जहां विस्तार कर्मी पीएमजेडीवाई में आर्थिक हस्तक्षेप दे सकते हैं।

....

....

....

....

....

....

....

....

16.5.2 अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, जैसे व्यक्तिगत नौकरानियों, ड्राइवरों और माली के लिए एक पेंशन योजना है। एपीवाई इन कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए पैसे बचाने में सहायता करने में मदद करता है। एक्सटेंशन पर्सनल संभावित लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंडों के बारे में सूचित कर सकता है। असंगठित क्षेत्र के लोग बैंक खाता खोलने के लिए बैंक से संपर्क करने में संकोच नहीं करते हैं। उनकी बचत भी बहुत कम हैय वे बैंक खाता खोलना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि, एपीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। यहां, एक्सटेंशन पर्सनल बैंक खाता होने के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करके उनकी मदद कर सकता है। पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति के पास आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है। आधार नंबर प्राप्त करने के लिए, विस्तार कर्मी उन्हें प्रक्रिया के बारे में सूचित कर सकते हैं। यहां एक्सटेंशन पर्सनल इन चीजों के बारे में जागरूकता पैदा कर सकता है और प्रशिक्षण आयोजित कर सकता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 6

नोटः 1) पाठ से परामर्श किए बिना प्रश्नों का उत्तर दें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें

1) एपीवाई की तीन प्राथमिक विशेषताएं दिखाएं जहां विस्तार कर्मी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं।

....

....

....

....

16.5.3 किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना

किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक ऐसी पहल है जो किसानों को समय पर ऋण तक पहुंच प्रदान करती है। केसीसी योजना यह सुनिश्चित करती है कि कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में किसानों को अल्पकालिक औपचारिक ऋण तक पहुंच हो।

पात्रता मानदंड और कार्ड की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता और ज्ञान की कमी के कारण किसानों का लाभ अभी तक नहीं हुआ है। यदि किसानों को केसीसी नहीं मिलता है, तो उन्हें वित्तीय रूप से लाभान्वित नहीं किया जाएगा। इसलिए, ग्रामीण विस्तार कर्मियों को केसीसी के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए और केसीसी प्राप्त करने के तरीके के बारे में बताना चाहिए। विस्तार कर्मी बटाईदारों के किसानों और किरायेदारों के किसानों को केसीसी प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह बनाने में मदद कर सकते हैं। वे बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए फसल उत्पादन योजना तैयार करने में उनकी मदद करते हैं। वे सहकर्मी दबाव भी बनाते हैं ताकि लाभार्थी ऋण का सही उपयोग कर सके और नियमित रूप से ऋण चुकाए।

16.5.4 कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)

केवीके आईसीएआर के तहत कृषि विकास का एक केंद्र है। प्रत्येक जिले में, केंद्र सरकार द्वारा एक केवीके स्थापित किया गया है। केवीके विस्तार शिक्षा की एक अवधारणा है, और विस्तार सिद्धांत का पालन करके पूरी गतिविधियां की जा रही हैं। केवीके का अधिदेश इसके अनुप्रयोग और क्षमता विकास के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रदर्शन है।

एक केवीके में, कृषि विषयों के विशेषज्ञों की छह संख्या होती है। अपने लक्ष्यों के अनुसार, उन्हें फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने और स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए खेल पर परीक्षण करने की आवश्यकता है। वे विषय वस्तु और विस्तार गतिविधियों के तरीकों के अपने ज्ञान को ताजा करने के लिए जमीनी स्तर के विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं। केवीके नई जारी किस्मों पर फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित करता है। विस्तार कर्मियों को केवीके के अन्य वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण, ऑन–फार्म ट्रायल और एफएलडी आयोजित करने में मदद करनी चाहिए। विस्तार कर्मियों को किसान मेला, फील्ड दिवस और एक्सपोजर विजिट के आयोजन करने में भाग लेना चाहिए।

अपनी प्रगति की जांच करें 7

नोटः 1) पाठ से परामर्श किए बिना प्रश्नों का उत्तर दें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) एक केवीके में, एक विस्तारवादी क्या भूमिका निभा सकता है?

....

....

....

....

16.5.5 पीएम किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, सभी किसान अपनी आय सहायता के रूप में हर साल 6,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं। सरकार सभी किसानों को संस्थागत ऋण और अधिक उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। यह किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और किसान सम्मान निधि योजनाओं को मिलाकर किया जाता है। एक किसान क्रेडिट कार्ड अब सभी किसान सम्मान निधि लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, विस्तार व्यक्तिगत योजना के लाभों और योजना के तहत वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने के तरीके के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा कर सकती है। एक्सटेंशन पर्सनल प्रभावी रूप से किसानों के बीच जागरूकता पैदा कर सकता है और उन्हें प्रक्रिया के बारे में सूचित कर सकता है। किसानों को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ इस योजना के बारे में किसानों की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। विस्तार कर्मी किसानों को डिजिटल बैंकिंग, लाभों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण और बैंक खाता खोलने और केसीसी के तहत पुनर्भुगतान के बारे में भी शिक्षित करते हैं।

16.5.6 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों के मृदा परीक्षण–आधारित और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि किसानों को कम लागत पर उच्च पैदावार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। मुख्य उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर संबंधित फसल के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा के बारे में उत्पादकों को जागरूक करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग को बनाए रखते हुए फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए शुरू की गई है। जब किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित उर्वरकों को लागू करते हैं, तो वे पैसे बचा सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

ज्यादातर मामलों में, यह देखा जाता है कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में पता नहीं है। इसलिए, विस्तार कर्मियों को जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण आयोजित करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड–आधारित सिफारिश का उपयोग करने की आवश्यकता है। जब विस्तार कर्मी इस प्रकार का हस्तक्षेप देते हैं, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड–आधारित सिफारिश में काफी वृद्धि होगी।

अपनी प्रगति की जाँच करें 8

नोटः 1) पाठ से परामर्श किए बिना प्रश्नों का उत्तर दें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) कैसे विस्तार कर्मी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसान को उनके आर्थिक विकास में मदद करते हैं।

....

....

....

....

....

16.5.7 दीन दयाल अंत्योदय योजना दृ एनआरएलएम

यह ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस उद्देश्य के लिए सरकार इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मानदण्डों का चयन करती है। यह योजना एक गरीब ग्रामीण परिवार की महिला सदस्यों के लिए प्रदान की जाती है। प्रत्येक चिन्हित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के तहत लाया जाता है। लक्ष्य समूह को खोजने के लिए गरीबों की भागीदारी पहचान (पीआईपी) दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। पीआईपी एक समुदाय–संचालित परियोजना होनी चाहिए। पीआईपी महत्वपूर्ण है, जिसे ग्रामीण गरीबों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए विस्तार कर्मियों द्वारा किया जा सकता है। विस्तार कर्मी योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कर सकते हैं और ग्रामीण गरीब महिलाओं को योजना से सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए संगठित कर सकते हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें 9

नोटः 1) नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) ग्रामीण गरीबों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एनआरएलएम में विस्तार कर्मियों द्वारा तीन हस्तक्षेप दिए गए थे।

....

....

....

....

....

....

....

16.5.8 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

पीएमकेवीवाई 3.0 (2020–21) योजना का प्राथमिक ध्यान अप–स्किलिंगध्री–स्किलिंग पर है, जो भविष्य के कौशल (उद्योग) पाठयक्रमों और कार्यबल उत्पादकता बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।

यह व्यापक कवरेज के लिए प्रशिक्षण के ऑनलाइन ध्‍ डिजिटल मोड पर केंद्रित है। यह मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार भी पेश करता है, जिसमें सामान्य मूल्यांकन केंद्र (सीएसी) और ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण शामिल हैं। विस्तार व्यक्तिगत रूप से बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर प्रचार कर सकता है, जिसमें मीडिया अभियान पुस्तिका और पैम्फलेट वितरण शामिल हैं;

जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। वे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने और अपनी आजीविका कमाने के लिए रोजगार योग्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। विस्तार व्यक्तिगत उद्योग की जरूरतों और समकालीन बाजार की मांग को पूरा करने के लिए लगातार कौशल अंतर सर्वेक्षण और विश्लेषण में भी मदद करता है। वे कौशल मेला, जागरूकता, और वकालत और प्रचार जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके लोगों को एक योजना से लाभ उठाने के लिए जुटा सकते हैं। इन हस्तक्षेपों के बिना, ग्रामीण लोगों को योजना से उचित लाभ नहीं मिलेगा और वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें 10

नोटः 1) नीचे दिए गए स्थान का उपयोग करें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) पाठ से परामर्श किए बिना प्रश्नों का उत्तर दें।

a) पीएमकेवीवाई 3.0 (2020–21) योजना को लाभान्वित करने के लिए विस्तार कर्मियों द्वारा किए गए कुछ हस्तक्षेपों की पहचान करें।

....

....

....

....

....

16.5.9 अम्ब्रेला एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)

महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने अम्ब्रेला आईसीडीएस के रूप में जाना जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम लागू किया। ये हैं:

a) आंगनवाड़ी सेवा योजना

b) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

c) राष्ट्रीय शिशु गृह योजना

d) किशोरियों के लिए योजना

e) बाल संरक्षण योजना

f) पोषण अभियान

आंगनवाड़ी सेवा योजना : एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह प्री–स्कूल अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की चुनौती के जवाब के रूप में अपने बच्चों और नर्सिंग माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का देश का सबसे स्पष्ट संकेत है। यह देश में अपने बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं के प्रति प्रतिबद्धता का सबसे स्पष्ट प्रतीक है जो भूख, रुग्णता, कम सीखने की क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ रही हैं।

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) : का लक्ष्य छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण/कुपोषण और एनीमिया को कम करके स्टंटिंग, अल्प–पोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के स्तर को कम करना है।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) : आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों के जवाब में, यह योजना 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान करती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान डीबीटी मोड में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) के बैंक/डाकघर खाते में तीन किस्तों में सीधे 5,000/– रुपये की राशि जारी की जाएगी।

किशोरी बालिका स्कीम में 11–14 आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि पोषण, जीवन कौशल और गृह कौशल के माध्यम से उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाया जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। इस स्कीम में पोषण और गैर–पोषण संबंधी घटक हैं, जिनमें पोषणय आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण शामिल हैं; स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाय पोषण और स्वास्थ्य शिक्षाय स्कूली छात्राओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा ब्रिज कोर्सध्कौशल प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए मुख्यधारा में लानाय जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन आदि; सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए परामर्श/ मार्गदर्शन।

राष्ट्रीय शिशु गृह योजना कामकाजी महिलाओं के 6 महीने से 6 साल के बच्चों को डे–केयर सुविधाएं प्रदान करती है। महीने में 26 दिन प्रतिदिन में साढ़े सात घंटे सुविधाएं दी जाती हैं । बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक बाल देखभाल शिक्षा, और स्वास्थ्य और सोने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

बाल संरक्षण सेवा योजना का उद्देश्य : चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बच्चों के सुधार और कल्याण में योगदान करना और स्थिति और कार्यों के प्रति कमजोरियों को कम करना है जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और माता–पिता से बच्चों के अलगाव का कारण बनते हैं। इस योजना का उद्देश्य बाल यौन शोषण सहित सभी बच्चों को किसी भी प्रकार के बाल शोषण से रोकने के तरीकों और साधनों के बारे में जागरूकता फैलाना है।

जब लाभार्थियों को कार्यक्रमों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाता है, तो वे सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जिससे वे स्वास्थ्य सेवा और पोषण संबंधी भोजन की लागत को कम कर सकते हैं। साथ ही, उन्हें सशक्त बनाया जाएगा, जो आय

सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। एक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से, विस्तार कार्यकर्ता लाभार्थियों की मदद कर सकते हैं। वे सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं।

16.5.10 जनजातीय लोगों के लिए योजनाएं

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत, आदिवासी लोगों के लिए कई योजनाएं हैं। उन्होंने आदिवासी छात्रों को उच्च स्तर तक अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए लक्षित किया। उस उद्देश्य के लिए, यह विभिन्न योजनाएं प्रदान करता है। चूंकि अधिकांश आदिवासी आबादी दूरदराज के क्षेत्रों में रहती है, इसलिए कई लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं है। यहां भी विस्तार कर्मी छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए उन्हें विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

16.5.11 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) को क्षेत्र–आधारित विकास को सक्षम करने के लिए लागू किया गया है। यह दृष्टिकोण एक आवश्यकता मूल्यांकन अभ्यास के आधार पर 'निगरानी योग्य संकेतकों' के बारे में जरूरतों या अंतराल का पता लगाता है। 'ग्राम विकास योजना' (वीडीपी) आवश्यकता मूल्यांकन अभ्यास के भाग के रूप में एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। यहां विस्तार कर्मी अपना हस्तक्षेप दे सकते हैं क्योंकि वे अंतर विश्लेषण में कुशल हैं।

16.5.12 महिला सशक्तिकरण योजनाएं

महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं हैं। यह परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा और महिलाओं के सशक्त होने पर ग्रामीण विकास में मदद करेगा। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करती है। हमारे समाज में महिलाओं को कम जानकारी मिलती है, क्योंकि अधिकांश डेटा उनके पुरुष समकक्षों को दिया जाता है। जब विस्तार कर्मी ग्रामीण महिलाओं को योजनाओं के बारे में सूचित करते हैं, तो वे लाभ उठा सकते हैं। जिससे वे उन्हें सशक्त बनाएंगे। एक बार जब कोई महिला सशक्त हो जाती है, तो वे विभिन्न आय पैदा करने वाली गतिविधियों को करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती हैं।

16.5.13 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

यह ग्रामीण परिवारों के व्यस्क सदस्यों को प्रति परिवार अधिकतम 100 दिन की काम शर्त पर अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। यह जिले के सभी गांवों पर लागू होता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मनरेगा के तहत पंजीकरण करने का अधिकार है।

मनरेगा में कई नियम–कानून हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का गारंटीशुदा काम मिलेगा। उस उद्देश्य के लिए, ग्रामीण गरीब जो अकुशल कार्य पर मैनुअल काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें जॉब कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि लाभार्थियों को 100 दिनों की गारंटीकृत काम नहीं मिल सकता है, तो उन्हें 100 दिनों के लिए मजूदरी भी मिलेंगे। हालांकि, अधिनियम में लाभार्थियों को कुल मजदूरी जारी करने का प्रावधान है यदि वे जॉब कार्डधारकों को 100 दिनों का काम प्रदान नहीं कर सकते हैं। उस उद्देश्य के लिए, लाभार्थियों को इसके लिए आवेदन करने की

आवश्यकता है। कुल मजदूरी का दावा करने के बारे में लाभार्थियों की उचित जानकारी की कमी लाभ प्राप्त नहीं करने का मुख्य कारण है। सफलता इस बात पर आधारित है कि ग्रामीण लोग सुविधाओं और प्रक्रियाओं को कैसे जानते हैं। इस प्रकार, विस्तार कर्मियों का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है।

अपनी प्रगति की जांच करें 11

नोटः 1) पाठ से परामर्श किए बिना प्रश्नों का उत्तर दें।

2) इकाई के अंत में दिए गए मॉडल उत्तर के साथ अपने उत्तर की तुलना करें।

1) मनरेगा क्या है?

....

....

....

....

....

16.6 आइए हम संक्षेप में बताएं

चर्चा को संक्षेप में कहें तो अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण लोगों का आर्थिक विकास है। हालांकि, कार्यक्रमों के अनुसार गतिविधियां अलग हैं। इच्छित लाभार्थी ऐसे आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे यदि वे कार्यक्रमों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानते हैं। कुछ कार्यक्रमों के लिए, लाभार्थियों को एक बैंक खाता खोलने, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्राप्त करने और स्वयं सहायता समूह बनाने की आवश्यकता होती है। विस्तार व्यक्तिगत जागरूकता निर्माण, सामाजिक लामबंदी, समूह गठन और समूह के प्रबंधन में कुशल हैं। इसलिए, यदि विस्तार कर्मी इन हस्तक्षेपों में शामिल हैं, तो इससे ग्रामीण लोगों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार के विस्तार कर्मियों के हस्तक्षेप के बिना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे।

16.7 खोजशब्दों

गरीबी : यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के पास न्यूनतम जीवन स्तर को वहन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था : यह प्राथमिक क्षेत्र और संबद्ध (शामिल) गतिविधियों की विशेषता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था उत्पादकों की अर्थव्यवस्था है।

आर्थिक रणनीति : इसमें विशिष्ट मुद्दों/समस्याओं को संबोधित करने और उनके दीर्घकालिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अद्वितीय अंतर्दृष्टि के साथ ग्राहकों को प्रदान करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों और तरीकों को लागू करना शामिल है।

आर्थिक हस्तक्षेप : परिणाम में हस्तक्षेप करने का कार्य, विशेष रूप से किसी स्थिति या प्रक्रिया का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय स्थिति में सुधार करता है।

16.8 सुझाए गए अध्ययन

विस्तार शिक्षा की पुस्तिका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (2020)

बी कुमार (2018) द्वारा विस्तार शिक्षा में नए रुझान। कल्याणी प्रकाशक

ग्रामीण विकास : सिद्धांत, नीतियां और प्रबंधन के सिंह (2009)। सेज प्रकाशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

16.9 आपकी प्रगति की जांच करने के लिए उत्तर

अपनी प्रगति की जांच करें I

1) गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के पास न्यूनतम जीवन स्तर को वहन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 2

1) ग्रामीण विकास का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण लोगों की भागीदारी के साथ ग्रामीण जीवन में सुधार करना है।

अपनी प्रगति की जांच करें 3

1) आर्थिक रणनीति में विशिष्ट मुद्दों/समस्याओंको संबोधित करने और उनके दीर्घकालिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ग्राहकों को अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों और तरीकों को लागू करना शामिल है। ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट आर्थिक रणनीतियों की आवश्यकता होती है जो सभी हितधारकों को संलग्न करती हैं, नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और उत्पादकता में सुधार करती हैं। यह एक सहयोगी रणनीति है– जो। यह मितव्ययिता या आर्थिक संकट में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है– प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और असतत सिफारिशों की लंबी सूची से आगे बढ़ने की आवश्यकता है । यहां विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 4

1) विकास के प्रवर्तक का मानना है कि ग्रामीण विकास के लिए सबसे उचित लक्ष्य स्थानीय लोगों का ''सशक्तिकरण'' है। अपनी मानव संसाधन क्षमताओं को मजबूत करके, एक विस्तार वंचित किसान संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को उचित विस्तार सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। संसाधन–गरीब किसान समूहों में से कई का शासन और नेतृत्व अनुभवहीन है। विस्तारवादी गरीब किसानों को बचत या उधार लेने में सक्षम बनाकर पूंजी प्राप्त करने में सहायता करने में सक्षम हो सकते हैं। वे किसान संस्थान बना सकते हैं, किसानों को संघों और कमोडिटी समूहों में व्यवस्थित कर सकते हैं, और अन्य सहकारी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं क्योंकि वे स्थानीय संगठन गठन में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। भारत के स्वयं सहायता समूहों में विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं जो कम लागत वाली वित्तीय सेवाएं और अन्य गतिविधियों को प्राप्त करने में 33 मिलियन भारतीय महिलाओं की सहायता करते हैं। ग्रामीण भारत में महिलाएं, विशेष रूप से निचली जातियों और शिक्षा के निम्न स्तर वाली महिलाओं को

खराब स्वास्थ्य और वित्तीय वस्तुओं को खरीदने में असमर्थता का सामना करना पड़ता है। भारत की ग्रामीण विकास पहल सूक्ष्म ऋण की आपूर्ति करके महिलाओं की आर्थिक स्थिति और अन्य कमजोर लोगों को विकसित करने पर केंद्रित है। ऋण प्राप्त करने के बाद ग्रामीण महिलाओं की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य बाधाओं को दूर करने के लिए कमजोर लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना है। एसएचजी स्थिरता के लिए, समुदाय बनाने, गतिशील समूह प्रबंधन और समूह लामबंदी के लिए विस्तार महत्वपूर्ण है। केवल स्थायी समूह ही सशक्तिकरण और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें 5

1) पीएमजेडीवाई समाज के गरीब वर्गों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। लोगों को इससे सहायता प्राप्त करने के लिए योजना प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कर्मी योजना द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्य और लाभों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के बीच जागरूकता पैदा कर सकते हैं। साथ ही, वे प्रत्येक बैंक के लिए सेवा क्षेत्र की मैपिंग के लिए बैंक नेटवर्क के साथ दूरदराज के क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं। विस्तार श्रमिकों को पता है कि ग्रामीण लोगों के पास अन्य हितधारकों की तुलना में बेहतर है, इसलिए सेवा विस्तार क्षेत्र की पसंद अधिक उद्देश्यपूर्ण होगी। डेबिट कार्ड, रूपे कार्ड का उपयोग करके, योजना से सहायता प्राप्त करने के लिए बैंक में खाता खोलें, विस्तारित लोगों द्वारा भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें 6

1) एपीवाई के तीन क्षेत्र जहां विस्तार कर्मी आर्थिक हस्तक्षेप दे सकते हैं, नीचे वर्णित हैं।

   असंगठित क्षेत्र के लोग उनके लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं से अनजान हैं। वे इस मामले में उन्हें प्रदान की गई सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं। नतीजतन, विस्तार कर्मी इस स्थिति में आवश्यक हस्तक्षेप करेंगे। वे संभावित लाभार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं और योग्यताओं की याद दिलाएंगे जिन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के लोग बैंक खाता खोलने के लिए बैंक से संपर्क करने में संकोच नहीं करते हैं। उनकी बचत भी बहुत कम है, और उस स्थिति में, वे बैंक खाता खोलना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। यहां, एक्सटेंशन पर्सनल उन्हें बैंक खाता खोलने में मदद कर सकता है।

अपनी प्रगति की जांच करें 7

1) केवीके की गतिविधियों में, विस्तार कर्मियों के पास कई आर्थिक हस्तक्षेप हैं। विस्तार कर्मियों को केवीके के अन्य वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण, ऑन–फार्म ट्रायल और एफएलडी आयोजित करने में मदद करनी चाहिए। विस्तार कर्मी किसान मेला, फील्ड दिवस और एक्सपोजर विजिट आयोजित करने में भाग ले सकते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें 8

1) यह देखा गया है कि किसानों को कई मामलों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में पता नहीं है और इसमें कम रुचि है। इसलिए, विस्तार कर्मियों को जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण आयोजित करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड–आधारित सिफारिश का उपयोग करने के लाभों की आवश्यकता है।

अपनी प्रगति की जांच करें 9

1) विस्तार कर्मी योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कर सकते हैं और ग्रामीण गरीब महिलाओं को योजना से सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए संगठित कर सकते हैं। विस्तार व्यक्तिगत ग्राम पंचायत की मदद कर सकता है, और ग्राम सभा पीआईपी विधि को लागू करके लाभार्थियों की पहचान करती है क्योंकि विस्तार कर्मी इस प्रकार के भागीदारी दृष्टिकोण के लायक हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें 10

1) पीएमकेवीवाई 3.0 (2020–21) योजना के लिए, विस्तार व्यक्तिगत रूप से पुस्तिका और पैम्फलेट वितरण सहित बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर प्रचार कर सकता है; मीडिया अभियान/जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। वे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने और अपनी आजीविका कमाने के लिए रोजगार योग्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एक्सटेंशन पर्सनल भी कौशल अंतर सर्वेक्षण में मदद करता है। और उद्योग की जरूरतों और समकालीन बाजार की मांग को संबोधित करने के लिए लगातार विश्लेषण। वे कौशल मेला जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके लोगों को एक योजना से मदद प्राप्त करने के लिए जुटा सकते हैं। जागरूकता और वकालत प्रचार। इस हस्तक्षेप के बिना, ग्रामीण लोग इस योजना से लाभान्वित नहीं होंगे। वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

अपनी प्रगति की जांच करें 11

1) यह अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है जो प्रति परिवार अधिकतम 100 दिनों के अधीन है। यह जिले के सभी गांवों पर लागू होता है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मनरेगा के तहत पंजीकरण करने का अधिकार है।